RAJYA SABHA

Friday, 28th April 1995/8th Vaisakha 1917 (Saka)

The House met at eleven of the clock. **Mr. Chairman** in the Chair.

Mid-day heals for KVS students

*361. SHRI RAGHAVJI:†
SHRI N. GIRI PRASAD:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration for providing mid-day meals for students of Kendriya Vidyalayas; and

(b) if so, the details thereof and; if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) and (b) No, Sir. The scheme of mid-day meals for the students has not been adopted by the Kendriya Vidyalaya Sangathan in the past because such a programme would require large resources which have not been available. Also, a pressing need for mid-day meals in Kendriya Vidyalaya Sangathan was not felt because school attendance and nutritional status of students have not been problem areas.

श्री राघव जी : सभापति जी, मेरा प्रश्न बहुत सीमित है । लेकिन उत्तर तो उससे भी अत्यन्त सूक्ष्म है । केन्द्रीय विद्यालय संगठन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा का चलाया जाने वाला संगठन है । यह एकमात्र संगठन है और इसीलिए इस संगठन को ऐसा होना चाहिए जो सारे राज्यों के लिए आदर्श बन सके और जिसका अनुपालन अन्य राज्य भी कर सकें । स्थापना के समय केन्द्रीय विद्यालय संगठन इस प्रकार का कार्य कर रहा था । लेकिन दुर्भाग्य से आज वह स्थिति नहीं रही है । अब इसमें बेहद अनियमितताएं, बेहद भ्रष्टाचार, अनेक शिकायतें हैं । यह एक प्रश्न अलग है । लेकिन माननीय मंत्री जी ने जवाब में बताया है कि इसके लिए प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता है । मध्यान्ह भोजन के लिए अगर केन्द्र सरकार यह व्यवस्था नहीं कर सकती जिसमें पूरे देश भर में केवल 7 लाख छात्र पढ़ते हैं, जबकि दिल्ली में कल घोषणा की गई है कि प्राईमरी स्कूल के छात्रों को जिनकी संख्या साढ़े सात लाख है, उनको मध्यान्ह का भोजन दिया जाएगा । तमिलनाडु में दिया जा रहा है । गुजरात सरकार प्रत्येक छात्र को जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनको... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please put your qquestion... (*Interruptions*)... Please put your question.

श्री राघवजी : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि संसाधनों की आवश्यकता है । जब छोटे छोटे राज्य संसाधनों की व्यवस्था कर रहे हैं तथा गुजरात 10 किलो अनाज छात्रों को देने जा रहा है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन में जितने छात्र स्कूली शिक्षा ले रहे हैं उनकी कुल संख्या कितनी है और कितने संसाधनों की आवश्यकता है और कुल बजट कितना है ? और यह व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती ? जबकि दिल्ली जैसा प्रदेश इसकी व्यवस्था कर रहा है तो यह व्यवस्था यहां भी क्यों नहीं हो सकती है ?

कुमारी शैलजा : सभापति जी, अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहूंगी । यह जो मिड-डे मील्स का प्रोग्राम है, अब तक हमने इसको जरूरी समझा है, बल्कि हमारे फाईनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में भी इसकी अहमियत पर जोर दिया है । हम पूरे देश के लिए मिड-डे

†The question was actually asked in the floor of the House by Shri Raghavji.

मील्स की एक स्कीम तैयार करने जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर । लेकिन जहां तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन की बात है, यह मिड-डे मील्स स्कीम की हम इसलिए जरूरत समझते हैं जिससे बच्चों की स्कूल में अटेंडेंस हम अच्छी कर सकें, और उनको सही तरह की न्यूट्रिशन दे सकें । हालांकि यह बहुत अच्छी स्कीम है और सभी बच्चों पर लागू होनी चाहिए, सभी बच्चों को देनी चाहिए और हर तरह के स्कूल में भी जानी चाहिए ।

आज के दिन जरूरत इस चीज की है कि सही तरीके से स्कूलों में अटेंडेंस हो और सही तरीके से न्यूट्रिशन दे सकें । जहां अटेंडेंस की कमी है और या न्यूट्रिशन की प्रोब्लम आती है वहां सबसे पहले इस स्कीम को लागू करते हैं इसीलिए यह स्कीम पूरे देश के लिए अनाउन्स की गई है । केन्द्रीय विद्यालय की जहां तक बात है मैंने अपने जवाब में पहले ही कहा है कि रिसोर्सेज को किस तरह से डिस्ट्रिब्यूट करना है उसके हिसाब से प्रियोरिटिज हम लेते हैं । केन्द्रीय विद्यालयों में हमने अभी इसको प्रेसिंग नीड नहीं समझा क्योंकि यहां अटेंडेंस प्रोब्लम नहीं देखी कि बच्चों को कैसे रिटेन किया जाए और दूसरे यह कि केन्द्रीय विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वे कम्पैरिटिव्ली अच्छे इकोनोमिक स्टेटस फेमिली से आते हैं । वे सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज के बच्चे होते हैं मैंने यह नहीं कहा कि यह स्कीम अच्छी नहीं है, लागू नहीं करनी चाहिए लेकिन अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखना पड़ता है ।

श्री राघवजी : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यह था क्या यह एक्सर्साइज किया गया है कि इसमें कितना खर्चा आयेगा । इसका जवाब नहीं आया ।

कुमारी शैलजा : प्राथमिकताओं के आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों को हमने इसमें नहीं लिया है । इसीलिए अभी तक स्टडी नहीं की गई है ।

श्री राघवजी : : सभापति महोदय, दूसरा पूरक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि माननीया मंत्री जी ने यह कहा है कि वहां पर इस तरह के विद्यार्थी आते हैं जो वैल टुडु फेमिली से आते हैं, मैं इससे मतभेद रखता हूं । इसमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में होते हैं । केन्द्रीय विद्यालय जहां-जहां चल रहे हैं उसमें 50 प्रतिशत स्कूल ऐसे स्थानों पर हैं जहां पर केवल मिलिटरी के जवान, साधारण सिपाही स्तर के बच्चे पढ़ते हैं । उसमें चपरासी के बच्चे भी पढ़ते हैं, खलासी के बच्चे भी पढ़ते हैं । इसलिए यह कहना कि इनमें ऐसे स्तर के बच्चे नहीं होते जिनको पोषण की आवश्यकता नही होती यह कहना गलत है । क्या कम से कम उन लोगों को जिनकी आय एक निश्चित मासिक सीमा के नीचे की हो उनको दोपहर का भोजन देने के लिए सरकार का विचार है जैसे कि गुजरात ने शुरू किया है कि दस किलो अनाज के कूपन प्रति माह दिये जायें ताकि वे अपना भोजन प्राप्त कर सकें । क्या गरीब विद्यार्थियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था करने का भविष्य में विचार किया जायेगा ? अगर नहीं तो क्यों नही ?

कुमारी शैलजा : मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगी कि मैंने यह नहीं कहा कि बच्चे वैल टुडु फेमिली से आते हैं । मैंने कहा था कि कम्पैरिटिव्ली, तुलनात्मक दृष्टि से वे थोड़े उस स्तर से बेहतर हैं । मैंने नहीं कहा कि वें ऐसे नहीं हैं, गरीब गरीब तबके से नहीं है । इसके अलावा और चीजें भी ध्यान में रखते हैं । अटेंडेंस की जहां तक बात है । इसके लिए आठवीं कक्षा तक शिक्षा फ्री की गई है और लड़कियों की 12वीं कक्षा तक शिक्षा फ्री की गई है । थोड़ी प्रियोरिटीज देखनी पड़ती हैं अपने रिसोर्सेज को देखते हुए । वैसे इसमें न करने की कोई बात नहीं थी ।

MR. CHAIRMAN: Shri Giri Prasad. Absent. Shri Upendra.

SHRI P. UPENDRA: Sir, the hon. Minister is right when she says that when the scheme has to be introduced,

Kendriya Vidyalayas cannot take priority because there is a lot of demand for admission in Kendriya Vidyalayas The drop-out rate in the other schools is much more compared to Kendriya Vidyalayas. In fact, there is no drop-out in Kendriya Vidyalayas. This scheme is intended as part of our efforts to stop the drop-out, to arrest it. The rural areas, particularly, are to get priority. There are two examples in this. One is the experiment done in Andhra Pradesh where the mid-day meal scheme was entrusted to teachers. The other is the Tamil Nadu experiment where it was handed over to private individuals *and private organisations. Tamil Nadu* has become successful, while Andhra has failed. Because the Government has already committed itself for this scheme, will the Minister examine both these examples and decide which pattern will be better for the scheme? In the Andhra experiment, the job was given to teachers. Instead of teaching, they were cooking the whole day and feeding children. That is why it failed. Therefore, she should examine both these examples and decide the pattern. Moreover, my suggestion is that the Mahila Samitis, the Gram Panchayats and the Parent-Teacher Associations, wherever they exist, they should be given the job to make it successful. Will the Minister consider these suggestions?

कुमारी शैलजा : माननीय सदस्य ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। हमने एक कमेटी बनायी है। यह स्कीम देश में कई राज्यों में, 13 राज्यों में किसी न किसी लेवल पर लागू की गयी है, मिड-डे-मील स्कीम तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश का भी उदाहरण अभी दिया है। एक कमेटी बनायी गयी है जो एजुकेशन सेक्रेटरी की चेयरमन-शिप में बनायी है । इसमें कई स्टेट्स के भी सेक्रेटरी हैं तथा गवर्नमेंट आफ इंडिया के सेक्रेटरी भी हैं। वे इस सारी स्कीम को देखेंगे और इसका एक्सपेंशन तथा मिड-डे-मील स्कीम के बारे में सारी चीजों को एक्जामिन करेंगे। आपने जो सुझाव दिए हैं वे बड़े अच्छे हैं और उन्हें भी वे देखेंगे।

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, recently, during elections in Andhra Pradesh, the hon. Prime Minister has promised to give 10 kgs. of free rice to the school children. Sir, there are about 3,500 SC|ST hostels in Andhra Pradesh. Is there any such proposal for mid-day meals for the SC|ST hostels in Andhra Pradesh? There are Navodaya Schools in every district headquarters in Andhra Pradesh. Is there any such proposal and will the Minister inform the House about the same?

कुमारी शैलजा : जहां तक नवोदय विद्यालयों का संबंध है वे रेजिडेंसियल स्कूल हैं। वहां पर वैसे ही सारे मील्स दिए जाते हैं। इस बारे में जैसा कि मैंने कहा, मिड-डे-मील स्कीम को वर्कआउट करने के लिए पूरे देश में फेज्ड मैनर में स्टेट्स गवर्नमेंट किस तरह से इसको लागू करें, ये सब चीजें यह कमेटी देखेगी।

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, I have not asked about the residential schools. There are many private hostels. There are Government hostels where about two lakh children are studying. There are hostels for the SC/ST students also. (*Interruptions*) Some BC hostels are also there. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Do they get food there?

कुमारी शैलजा : वैसे मैं जवाब केन्द्रीय विद्यालयों के बारे में दे रही थी लेकिन इन्होंने दूसरी चीज पूछी है। इसलिए मैंने कमेटी का जिक्र किया है। मैं अपने आप को उस तक ही कनफाइन करना चाहती हूं जिसका जवाब इस प्रश्न से उठता है।

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: What about the assurance given by the Prime Minister during election time? I am asking about that. He has promised to give 10 kgs. of free rice. (*Interruptions*)

KUMARI SELJA: That is why I referred to that. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: This is a little outside the scope of the Question.

श्रीमती सरला महेश्वरी : माननीय सभापति महोदय, स्कूलों में मध्याह्न भोजन देने के लिए यह योजना तीन मुख्य उद्देश्यों से शुरू की गयी थी। ड्राप आउट रेट कम करने के लिए, इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए और गरीब बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए। इन्हीं तीन उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए पहली योजना तमिलनाडु में 1956 में शुरू की गयी थी उसके बाद अन्य राज्यों में भी शुरू हुई। सभापति महोदय, मेरे पास एक सर्वे रिपोर्ट है। 1992 के एकानामिक एंड पोलिटिकल वीकली में मध्याह्न भोजन का सारे देश में क्या प्रभाव पड़ा है, इसका सर्वे किया गया है और उस सर्वे रिपोर्ट से जो मुख्य निष्कर्ष निकलता है, उसका जो परिणाम आया है वह यह है कि मध्याह्न भोजन से इनरोलमेंट में वृद्धि हुई है, ड्राप-आउट में कमी हुई और गरीब बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ है। खासकर यह प्रभाव देहातों से और शहरों की बस्तियों में हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि इन निष्कर्षों को देखते हुए क्या वे तमाम राज्य सरकारों को, जो मध्याह्न भोजन की योजनायें गांवों में लागू कर रहे हैं, शहरों की बस्तियों में लागू कर रहे हैं लेकिन धनाभाव के कारण केन्द्रीय सरकार की केन्द्रीयकरण की जो योजना है, उसके चलते सारी की सारी क्षमताओं को जो केन्द्रीय सरकार के हाथ में केन्द्रित किया जा रहा है–मंत्री महोदया ने सही कहा है कि हम अपने संसाधनों को प्राथमिकता के आधार पर खर्च करना चाहते हैं, तो इस प्राथमिकता के सवाल को उठाते हुए मैं आप से यह सवाल करना चाहूंगी कि क्या आप उन राज्य सरकारों को जो राज्य सरकारें इस स्कीम को लागू कर रही हैं उनको आर्थिक संसाधन मुहैया करायेंगी? मैं यहां पर पश्चिम बंगाल का खासतौर से उदाहरण देना चाहूंगी। सभापति महोदय पश्चिम बंगाल में पिछले चार वर्षों में साक्षतरता की वृद्धि दर जिस अनुपात में बढ़ी है वह देश में सबसे अधिक है। वहां पर भी आर्थिक अभाव महसूस किया जा रहा है। उन राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता मुहैया करने के लिए सरकार के पास क्या योजना है ताकि हमारी राज्य सरकारें यह जो प्राथमिक काम है, इस प्राथमिक काम को वरीयता दे कर आगे बढ़ा सकें। इस संबंध में आपकी क्या राय है?

KUMARI SELJA: Sir, with your permission, may I quote from the Budget speech of the Finance Minister?

माननीया सदस्या ने जो कहा है, इन्होंने खुशी जाहिर की है और बताया है कि मिड-डे-मील्ज स्कीम से क्या अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में कहा है जिसके कारण हम यह स्कीम ले रहे हैं। मैं कोट करना चाहूंगी–

"'Schemes to provide mid-day meals for school children have a beneficial impact not only on child nutrition but also on school attendance. Some of the State Governments have been operating school mid-day meals schemes. As part of the emphasis being laid by this Government on primary education and taking into account the comfortable food stocks with the public sector agencies, it is appropriate that the Central Government should be willing to participate in phased expansion of these schemes."

इसलिए हम भी चाहते हैं, गवर्नमेंट आफ इण्डिया भी इसमें कंट्रीब्यूशन दे और इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है जो इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगी कि कैसे गवर्नमेंट आफ इण्डिया स्टेट्स की मदद कर सकती है। हम भी मदद करना चाहते हैं और जाहिर है कि बच्चों के लिए यह बहुत अच्छी स्कीम है। इसको हम फेज्ड एक्सपेंशन में लागू करेंगे।